

# इंडियन एक्सप्रेस न्यूज विश्लेषण (आईना)

## हिंदी पीडीएफ नोट्स - 01 जून 2023

### सहकारी क्षेत्र में 'सबसे बड़ी' अनाज भंडारण योजना स्थापित करने के लिए अंतर-मंत्रालय पैनल को कैबिनेट की मंजूरी

#अनाज भंडारण योजना #सहकारी क्षेत्र #सरकारी योजना #शासन #सामान्य अध्ययन2

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को तीन मंत्रालयों की चल रही आठ योजनाओं को मिलाकर "सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना" बनाने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) के गठन और अधिकार को मंजूरी दे दी।

मंत्रिमंडल के फैसले के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, "हम करीब एक लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू करेंगे।

सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया जाएगा, जिसमें कृषि और किसान कल्याण, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री और सचिव सदस्य होंगे।

### 8 SCHEMES IDENTIFIED FOR CONVERGENCE

#### Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare

- Agriculture Infrastructure Fund (AIF)
- Agricultural Marketing Infrastructure Scheme (AMI)
- Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH)
- Sub-Mission on Agricultural Mechanization (SMAM)

#### Ministry of Food Processing Industries

- Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises Scheme
- Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana (PMKSY)

#### Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution

- Allocation of food grains under the Food Security Act
- Procurement ops at MSP

### कैबिनेट ने स्मार्ट शहरों में सर्कुलर इकोनॉमी (चक्रीय अर्थव्यवस्था) के लिए योजना को मंजूरी दी

#CITIIS2.0 #स्मार्ट शहर #चक्रीय अर्थव्यवस्था #अपशिष्ट प्रबंधन #सरकारी योजना #शासन #सामान्य अध्ययन2

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक प्रतियोगिता के माध्यम से चुने जाने वाले 18 स्मार्ट शहरों में सर्कुलर इकोनॉमी (चक्रीय अर्थव्यवस्था) को बढ़ावा देने के लिए सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इन्वेशन, इंटीग्रेटेड एंड सस्टेन (सीआईटीआईआईएस) 2.0 को मंजूरी दे दी।

इस योजना के लिए कुल वित्त पोषण - 1,760 करोड़ रुपये - फ्रांसीसी विकास एजेंसी (एएफडी) और एक जर्मन विकास बैंक क्रेडिटनस्टाल्ट फर विडरोफबाउ (केएफडब्ल्यू) से ऋण से आएगा; और यूरोपीय संघ से 106 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

कार्यक्रम इस साल शुरू होगा और राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के समर्थन से 2027 तक चलेगा।

इस कार्यक्रम में शहर स्तर पर एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन, राज्य स्तर पर जलवायु-उन्मुख सुधार कार्य और राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत सुदृढीकरण और ज्ञान प्रसार पर ध्यान केंद्रित करने के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाली प्रतिस्पर्धी रूप से चयनित परियोजनाओं का समर्थन करने की परिकल्पना की गई है।

कार्यक्रम की पहली पुनरावृत्ति, सीआईटीआईआईएस, 2018 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, एएफडी, यूरोपीय संघ और एनआईयूए द्वारा 933 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ शुरू किया गया था। इसके लिए 100 स्मार्ट शहरों में से 12 शहरों का चयन किया गया था।

आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के एक सूत्र के अनुसार, इस योजना के माध्यम से वित्त पोषित की जाने वाली परियोजनाएं हस्तांतरण स्टेशनों सहित कचरे का संग्रह और परिवहन होंगी; स्वचालित वसूली सुविधाएं; जैव-मीथेनेशन पौधे; निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र; और सैनिटरी लैंडफिल शामिल होंगी।

एक चक्रीय अर्थव्यवस्था में ऐसे बाजार शामिल होते हैं जो उत्पादों को खत्म करने और फिर नए संसाधनों को निकालने के बजाय उनके पुनः उपयोग के लिए प्रोत्साहन देते हैं। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) के अनुसार, ऐसी अर्थव्यवस्था में, कचरे के सभी रूप, जैसे कपड़े, स्क्रैप धातु और अप्रचलित इलेक्ट्रॉनिक्स, अर्थव्यवस्था में वापस आ जाते हैं या अधिक कुशलता से उपयोग किए जाते हैं।

देश के प्रत्येक क्षेत्र - उत्तर, उत्तर-पूर्व, पूर्व, मध्य, पश्चिम और दक्षिण से कम से कम एक शहर का चयन किया जाएगा।

## विश्व तंबाकू निषेध दिवस: सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तंबाकू चेतावनियों का प्रदर्शन अनिवार्य किया

#तंबाकू चेतावनी #विश्व तंबाकू निषेध दिवस #ओटीटी प्लेटफॉर्म #डिजिटल मीडिया विनियमन #डिजिटल भारत #अर्थव्यवस्था #सामान्य अध्ययन3

सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्मों के लिए स्ट्रीम की गई सामग्री के बीच और बीच में तंबाकू से जुड़ी स्वास्थ्य चेतावनियों को प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को एक अधिसूचना में यह घोषणा की, जिसे विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया गया।

ऐसे स्वास्थ्य स्थल और तंबाकू से संबंधित चेतावनियां पहले से ही स्क्रीनिंग के दौरान फिल्म थिएटरों द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं।

हमारे पास पहले से ही टीवी और फिल्मों में तंबाकू उत्पादों के चित्रण पर प्रतिबंध पर दिशानिर्देश हैं और अब हमारे पास यह ओटीटी प्लेटफॉर्मों के लिए भी है। इस तरह के प्रयास महत्वपूर्ण हैं क्योंकि देश में हर साल लगभग 13.5 लाख मौतों को किसी न किसी तरह से तंबाकू के सेवन से जोड़ा जा सकता है।

इस वर्ष के विश्व तंबाकू निषेध दिवस का विषय - "हमें भोजन की आवश्यकता है, कोई तंबाकू नहीं" – इस तर्क का विरोध करता है कि तंबाकू नियंत्रण से किसानों की आजीविका का नुकसान होगा।

अधिसूचना के अनुसार, समाचार और करंट अफेयर्स सामग्री के अलावा ऑनलाइन व्दरेटेड सामग्री के सभी प्रकाशकों को कार्यक्रमों की शुरुआत और बीच में कम से कम 30 सेकंड के लिए एक स्वास्थ्य स्थान प्रदर्शित करना होगा।

जब स्क्रीन पर एक तंबाकू उत्पाद दिखाई देता है, तो इसे स्क्रीन के निचले भाग में एक प्रमुख स्थिर स्वास्थ्य चेतावनी के साथ होना होगा।

प्लेटफार्मों को कार्यक्रमों की शुरुआत में और बीच में तंबाकू के उपयोग के दुष्प्रभावों पर कम से कम 20 सेकंड का ऑडियो-विजुअल डिस्कलेमर चलाने के लिए भी कहा गया है।

स्वास्थ्य स्पॉट और अस्वीकरण सामग्री के समान भाषा में होना चाहिए।

अधिसूचना के अनुसार, स्वास्थ्य मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधियों वाली एक अंतर-मंत्रालयी समिति उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए या शिकायत मिलने पर कार्रवाई करने के लिए अधिकृत होगी।

## महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर किया जाएगा

#अहिल्या नगर #अहमदनगर का नाम परिवर्तन #राज्य समाचार #राज्यव्यवस्था #सामान्य अध्ययन2

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर की 298वीं जयंती मनाने के लिए अहमदनगर का नाम बदलने की घोषणा की। इस नाम बदलने के महत्व को समझने के लिए अहमदनगर नाम के पीछे के इतिहास को जानना जरूरी है। महाराष्ट्र में स्थित अहमदनगर की एक समृद्ध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। इस क्षेत्र के संदर्भ 240 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक से पता लगाए जा सकते हैं।

मध्ययुगीन काल में, इस क्षेत्र पर राष्ट्रकूट, पश्चिमी चालुक्य और दिल्ली सल्तनत जैसे विभिन्न राजवंशों का शासन था। यह इस समय के दौरान था कि एक अफगान सैनिक अल्लादीन हसन गंगू द्वारा विद्रोह ने दक्कन में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। बहमनी साम्राज्य से पांच स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, जिनमें से एक निजामशाही था, जिसे बाद में अहमदनगर के नाम से जाना जाने लगा। 1486 में, मलिक अहमद निजाम शाह बहमनी सल्तनत के प्रधान मंत्री बने। उन्होंने 1490 में बहमनी साम्राज्य के राजा के खिलाफ अपनी स्थिति का सफलतापूर्वक बचाव किया और अपनी जीत के स्थल के पास, सिना नदी के बाएं किनारे पर एक शहर की स्थापना की। उनके सम्मान में इस शहर का नाम अहमदनगर रखा गया।

निजाम शाह ने बाद में दौलताबाद के किले पर कब्जा कर लिया और वहां अपनी सेना तैनात कर दी। दूसरी ओर अहिल्याबाई होलकर का जन्म अहमदनगर के चोंडी गांव में हुआ था। उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, जो उस समय महिलाओं के लिए दुर्लभ थी, उनके पिता, मनकोजी शिंदे की बदौलत, जो ग्राम प्रधान थे। अहिल्याबाई ने पेशवा बाजीराव के सेना कमांडर मल्हार राव होलकर का ध्यान तब खींचा था, जब वह सिर्फ आठ साल की थीं। उसकी भक्ति और चरित्र से प्रभावित होकर, उसने अपने बेटे, खांडे राव के लिए उससे शादी करने की व्यवस्था की। 1754 में कुंभेर की लड़ाई में अपने पति की मृत्यु के बाद, अहिल्याबाई ने मालवा पर नियंत्रण कर लिया। अपने ससुर के मार्गदर्शन में, उन्होंने असाधारण प्रशासनिक और सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया। वह अपने लोगों का नेतृत्व करने में विश्वास करती थीं और खांडे राव के निधन के बाद सती प्रथा का पालन नहीं करती थीं। अपने ससुर और बेटे की मृत्यु के बाद, अहिल्याबाई ने अपनी सेना का समर्थन मांगा और मालवा का शासक बनने के लिए पेशवा को याचिका दी। अहिल्याबाई होलकर को एक दूरदर्शी शासक के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने अपने लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न सुधारों और पहलों को लागू किया। अहमदनगर का नाम उनके नाम पर रखना उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए एक श्रद्धांजलि है और एक सम्मानित रानी और प्रशासक के रूप में उनकी विरासत का सम्मान करना है।

## सेना, नौसेना, वायु सेना के लिए कार्ड पर अतिरिक्त संयुक्त रसद नोड्स

#अतिरिक्त संयुक्त रसद नोड्स #रक्षा #सामान्य अध्ययन3

सशस्त्र बल अपनी रसद आवश्यकताओं में एकीकरण को बढ़ावा देने और अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए देश भर में अतिरिक्त संयुक्त रसद नोड्स स्थापित करने की योजना बना रहे हैं।

अब तक, भारत में तीन संयुक्त रसद नोड्स थे जिन्हें 2021 में तीनों सेवाओं के रसद एकीकरण के लिए चालू किया गया था। मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ के तहत संयुक्त संचालन प्रभाग नोड्स की स्थापना के लिए जिम्मेदार रहा है।

पिछले संयुक्त लॉजिस्टिक नोड को अप्रैल 2021 में मुंबई में पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत द्वारा संचालित किया गया था, जबकि गुवाहाटी और त्रि-सेवाओं, अंडमान और निकोबार कमान, पोर्ट ब्लेयर में जनवरी 2021 में परिचालन किया गया था।

अब तीन और संयुक्त रसद नोड्स स्थापित करने की योजना है जो जल्द ही लेह, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में स्थापित होने की संभावना है।

ये नोड्स सशस्त्र बलों को उनके छोटे हथियारों के गोला-बारूद, राशन, ईंधन, जनरल स्टोर, नागरिक किराए के परिवहन, विमानन कपड़े, पुर्जों और इंजीनियरिंग सहायता के लिए एकीकृत रसद कवर प्रदान करेंगे, इस प्रकार उनके परिचालन प्रयासों को एकीकृत करेंगे, खासकर संघर्ष या युद्ध के दौरान।

स्थानों का चयन रेल और हवाई बुनियादी ढांचे से उनकी निकटता को ध्यान में रखते हुए किया गया था, जबकि यह सुनिश्चित किया गया था कि किसी भी आकस्मिक स्थिति में स्टोर के प्रसार के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध है।

इन नोड्स के लिए स्टॉकिंग नीति का मसौदा क्षेत्र में तैनात सैनिकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा, साथ ही किसी भी वृद्धि को ध्यान में रखा जाएगा जिसे विशेष रूप से पहाड़ों में करने की आवश्यकता हो सकती है। यह मौसम और अन्य चुनौतियों को भी देखेगा, जिससे कुछ क्षेत्र कट जाते हैं और इस प्रकार पुनः आपूर्ति प्रभावित होती है। नीति गोला-बारूद के समय पर कारोबार को ध्यान में रखेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका उपयोग उनके निर्दिष्ट शेल्फ जीवन के भीतर किया जाए।

## देश के विभिन्न हिस्सों में कक्षा 11-12 के छात्र किन विषयों का चयन करते हैं

[#विद्यालयी विषय](#) [#विद्यालयी शिक्षा](#) [#परख](#) [#एनसीईआरटी](#) [#शिक्षा](#) [#अर्थव्यवस्था](#) [#सामान्य अध्ययन3](#)

केंद्र सरकार ने भारत में हाई स्कूल स्तर पर शैक्षणिक धाराओं की पसंद में क्षेत्रीय विविधताओं को समझने के लिए एक अध्ययन किया। अध्ययन ने विभिन्न राज्यों, विशेष रूप से दक्षिण भारत में विज्ञान, कला और वाणिज्य धाराओं के लिए वरीयता पर ध्यान केंद्रित किया। अध्ययन के निष्कर्षों से पता चला है कि अधिकांश दक्षिणी राज्यों में विज्ञान पसंदीदा धारा है, जबकि इन क्षेत्रों में कला की सीमित लोकप्रियता है। सरकार ने इस तरह की असमानताओं को दूर करने और क्षेत्रों में संतुलित शैक्षिक अवसरों को बढ़ावा देने के लिए एनसीईआरटी के तहत परख डिवीजन की स्थापना की।

अध्ययन ने शीर्ष राज्यों की पहचान की जहां विज्ञान स्ट्रीम लोकप्रिय है, जिनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और केरल शामिल हैं। पूर्वोत्तर में, मणिपुर विज्ञान का चयन करने वाले छात्रों के उच्च प्रतिशत के साथ सबसे ऊपर था। दूसरी ओर, गुजरात, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में कला पसंदीदा विकल्प थी। पूर्वोत्तर में, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में कला के लिए एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता थी।

अध्ययन ने पिछले एक दशक में कॉमर्स स्ट्रीम के स्थिर विकास पर भी प्रकाश डाला, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर इस अनुशासन को चुनने वाले छात्रों का अपेक्षाकृत कम प्रतिशत था।

इसके अलावा, अध्ययन ने उच्च शिक्षा के रुझानों की जांच की और संकेत दिया कि दक्षिण भारत विज्ञान शिक्षा के लिए एक मजबूत प्राथमिकता प्रदर्शित करता है। इस क्षेत्र में एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थानों की एक बड़ी संख्या है, जिसमें तमिलनाडु में इंजीनियरिंग और तकनीकी पाठ्यक्रमों का पीछा करने वाले छात्रों की संख्या सबसे अधिक है। चिकित्सा शिक्षा के संदर्भ में, दक्षिणी राज्यों तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में एक महत्वपूर्ण उपस्थिति है, जो देश में मेडिकल कॉलेजों के काफी अनुपात के लिए जिम्मेदार है।

जेईई एडवांस्ड और जेईई मेन जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों के प्रदर्शन ने दक्षिण भारत में विज्ञान शिक्षा के लिए वरीयता को भी दर्शाया, जिसमें उल्लेखनीय उपलब्धियां और क्षेत्र के छात्रों से उच्च स्कोर थे।

सरकार ने शैक्षिक अवसरों में असमानताओं को दूर करने और क्षेत्रों में समान विकास को बढ़ावा देने के लिए इस अध्ययन को आयोजित करने का विकल्प चुना। इसका उद्देश्य विभिन्न शिक्षा बोर्डों के बीच मूल्यांकन में समानता लाना और छात्रों के बीच शैक्षणिक धाराओं की पसंद को प्रभावित करने वाले कारकों को समझना था।

## व्यक्तिगत और राजनीतिक: नेपाल से, प्रचंड की भारत यात्रा को पढ़ रहे हैं

#भारत नेपाल संबंध #द्विपक्षीय संबंध #भारत और उसके पड़ोसी देश #अंतरराष्ट्रीय संबंध #सामान्य अध्ययन2

नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड चार दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। अपनी यात्रा के दौरान, वह दोनों देशों के बीच ऊर्जा, व्यापार और कनेक्टिविटी में सहयोग पर चर्चा करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे।

काठमांडू से रवाना होने से पहले राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने नेपाल के नागरिकता कानून में एक विवादास्पद संशोधन को मंजूरी दी थी। यह संशोधन नेपालियों से विवाहित विदेशी महिलाओं को लगभग तत्काल नागरिकता और राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है। इस कदम से नेपाल के नागरिकता कानून को दुनिया के सबसे उदार कानूनों में से एक बनाने की उम्मीद है। हालांकि, यह चीन को भी परेशान कर सकता है, जिसने तिब्बती शरणार्थियों के वंशजों को नागरिकता और संपत्ति का अधिकार देने वाले कानून के बारे में चिंता व्यक्त की है।

ऐतिहासिक रूप से, नेपाल और भारत के बीच राज्य के प्रमुखों / सरकारों के प्रमुखों द्वारा पारस्परिक यात्राएं एक द्विपक्षीय परंपरा थी। हालांकि, 1997 के बाद से, भारत ने पारस्परिक यात्रा किए बिना नेपाली नेताओं की मेजबानी की है। इसके परिणामस्वरूप नेपाल में चीन और पश्चिमी देशों की भूमिका बढ़ गई है जो देश में अपनी उपस्थिति और प्रभाव बढ़ाने के लिए कदम उठा रहे हैं। कभी चीन समर्थक माने जाने वाले प्रचंड अब चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए भारत को उनके साथ गठबंधन करने की इच्छा का आश्वासन दे सकते हैं। वह भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं और नेपाली हिंदू भावनाओं के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए अपने यात्रा कार्यक्रम में महत्वपूर्ण हिंदू धार्मिक स्थलों की यात्रा को शामिल किया है।

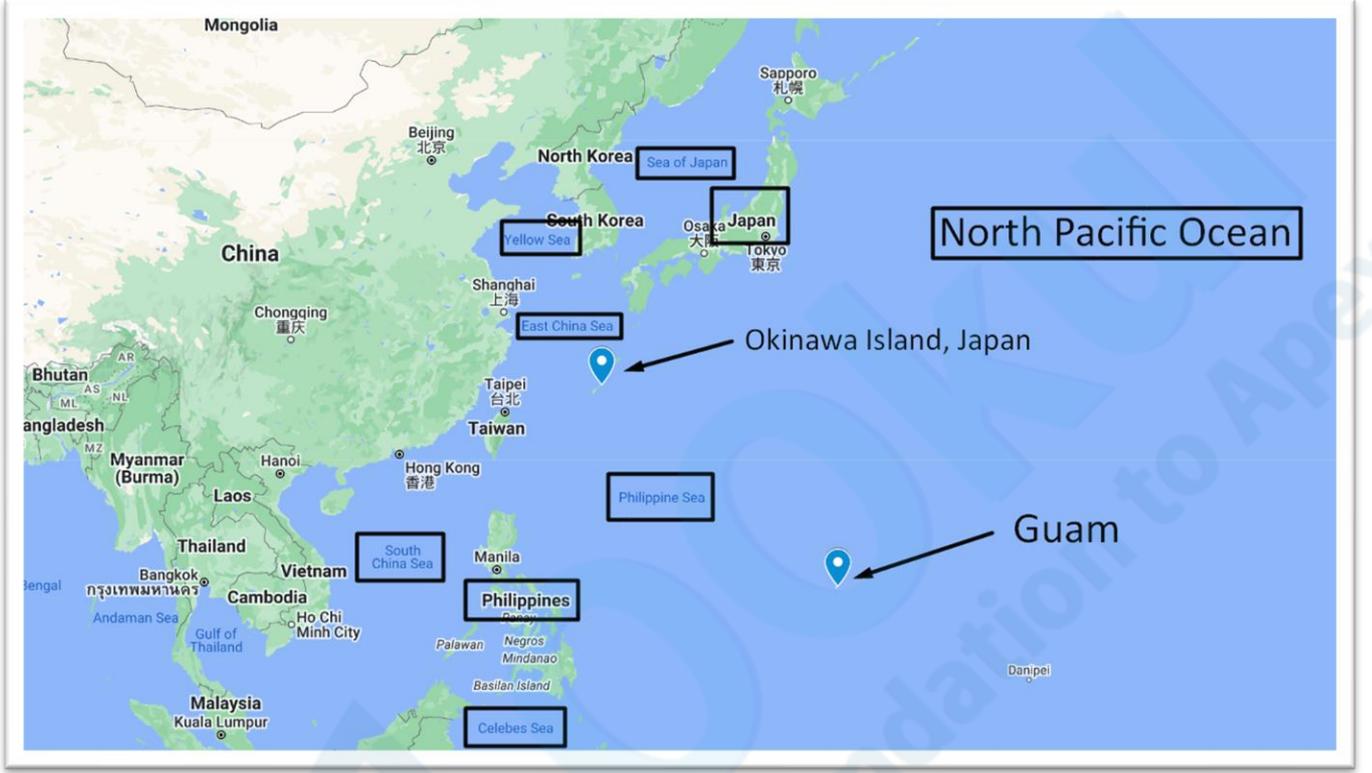
नेपाल में भारत द्वारा निष्पादित जल विद्युत परियोजनाओं के आसपास घर्षण के बिंदुओं को संबोधित करने के प्रयास किए गए हैं। अपने पूर्ववर्ती की तरह वर्तमान प्रधानमंत्री भी चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के तहत उन परियोजनाओं को लेकर सतर्क रहे हैं, जिन पर नेपाल ने छह साल पहले सहमति जताई थी। दहल का उद्देश्य खुद को भारत के दोस्त के रूप में चित्रित करना और चीन के साथ अपने पिछले संरेखण पर द्विपक्षीय संबंधों को प्राथमिकता देना है।

## ओकिनावा की तरफ बढ़ रहा तूफान मेवाड़ कमजोर पड़ा

#तूफान मेवाड़ #ओकिनावा द्वीप समूह #गुआम #अंतरराष्ट्रीय मामले

ताइवान और फिलीपींस को पीछे छोड़ने के बाद तूफान मेवाड़ बुधवार को जापान के ओकिनावा द्वीप समूह की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका की एक महत्वपूर्ण सैन्य उपस्थिति है।

पिछले हफ्ते गुआम को पार करने के बाद मेवाड़ मंगलवार को 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं और 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ ताइवान के पास से गुजरा, जिससे द्वीप के पूर्वी तट पर ऊंची लहरें उठीं।



## सरकार का राजकोषीय घाटा 2022-23 में जीडीपी के 6.4% तक कम हुआ

#राजकोषीय घाटा #सकल घरेलू उत्पाद #अर्थव्यवस्था #सामान्य अध्ययन3

वित्त वर्ष 2022-23 में केंद्र का राजकोषीय घाटा कम होकर जीडीपी का 6.4 प्रतिशत रह गया, जो वित्त वर्ष 2022 में 6.71 प्रतिशत था।

केंद्रीय बजट में सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 5.9 प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य रखा है।

लेखा महानियंत्रक (सीजीए) ने 2022-23 के लिए केंद्र सरकार के राजस्व-व्यय के आंकड़ों का खुलासा करते हुए कहा कि राजकोषीय घाटा पूर्ण रूप से 17,33,131 करोड़ रुपये (अंतिम) था, जो बजट में संशोधित अनुमानों (आरई) में अनुमानित राशि से मामूली कम है।

-----X-----X-----X-----